13.37 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT ORDINANCE AND INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT BILL—contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion of the followig resolution moved by Shri Madhu Limaye on the 29th August, 1974, namely:—

"This House disapproves of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No 4 of 1974) promulgated by the President on the 28th June, 1974.

and also further consideration of the following motion moved by Shri K. D Malaviya on the 29th August, 1974, namely:—

"That the Bill to amend the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Shri Bhogendra Jha who was on his legs may now continue his speech.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था आइ० आइ० एस० को० को अपने प्रबन्ध में लेने के लिये अगले तीन साल तक और फिर अगले 5 साल तक के लिये अवकाश छोड़ने से बहुत सी दिक्कतें पैदा होंगी। इस बीच में सरकार जो उस के उत्पादन की वृद्धि के लिये, सुधार के लिये उस में लगायेगी उस से उस की कीमत बढ़ेगी और जिन प्रबन्धकों ने पहले उस को बुरी हालत में पहुचा दिया जिस के लिये बहुत बड़ा जालसाजी का मामला चला और मुकदमा भी चल रहा है श्री आर० एन० गोयनका पर और जैसा प्रधान मत्री ने कहा था कि एक बिजनेसमेन ने धमकी दी थी कि अगर मुकदमा नहीं उठाया गया तो बिहार में उपद्रव होगा, और जहा तक हमें पता है वह व्यापारी गोयनका ही है और जो बिहार गये भी थे तो ऐसी स्थिति मे मेरा कहना यह है कि यह बहुत ही निराशा की बात है कि सफलतापूर्वक आइ० आइ० एस० को० को चलाने के बाद अब मत्री महोदय सिर्फ उस के प्रबन्ध को अपने हाथ मे लेने के लिये तीन साल के लिये जा रहे है। आवश्यकता इस बात की है कि फौरन उस का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय जिस से भ्रष्ट और उत्पादन को ठप्प करने वाले प्रबन्धकों को या पुराने मालिकों को सहारा न मिले बल्कि उस कारखाने का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर ले।

13.39 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

इसी प्रसग में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहूगा कि जो भारत बेग्ल, बम्बई मे है और जापान ग्रुप जिस के मालिक है वह चार साल से बन्द पड़ा हुआ है और उस के दस हजार से ऊपर एम्पलाइज बेकार पड़े हुए है, तो फिर उस का राष्ट्रीयकरण क्यों नही कर दिया जाता और उस के प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ मे क्यो नही ले लेती ताकि बेग्ल का उत्पादन हो।

इसी पृष्ठभूमि मे एक बात और कहना चाहूगा और मैं चाहूगा कि मत्री जी इस बात पर ध्यान दे। इस का प्रबन्ध आप ने लिया और उस मे प्रगति हुई लेकिन अभी तक उस के प्रबन्ध का तरीका पुराना है। क्या इस बात की आवश्यकता नही है कि जो प्रबन्ध बोर्ड के लिए सुझाव दिया गया है, उस मे श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व रहे। जिन श्रमिकों ने इस की खराब हालत को सुधार कर अच्छी हालत मे कदम बढ़ाया है, तो उस के प्रबन्ध के लिए जो बोर्ड बनेगा, उस मे श्रमिको के प्रतिनिधित्व को कोई गुंजाइश न रखे, तो यह ठीक नही होगा। इसलिए मैं मंत्री

जी से आग्रह करूंगा कि जो बोर्ड बनाया जाए उस में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और चुनाव के जरिये से उस को लिया जाए।

मैं इस आग्रह के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि इसको अपने हाथ में लेने से ही आप संतुष्ट न हो जाए, बल्कि उसका फौरन राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए और श्रमिकों का सहयोग प्रबन्ध में लेना चाहिए और वहां पर जो पुराने आफिसर्स हैं जो कि पुराने प्रबन्धकों के मातहत थे और जिन का उत्पादन को बढ़ाने में इन्ट्रेस्ट नहीं है और जो छिप कर उत्पादन में बाधा डालते हैं, उन को हटा कर प्रबन्ध में ऐसे आफिसर्स रखे जाएं जिन का विश्वास पब्लिक सैक्टर में है और जो उत्पादन बढ़ाने में विश्वास रखते हैं।

मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि आप उस का राष्ट्रीयकरण करने की ओर कदम बढ़ाएं और श्रमिकों का सहयोग मंत्री महोदय प्रबन्ध में लें।

श्री राम सहाय पांडेय (राजनदगाव) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता। मालवीय जी के हाथों में और इन के उत्तरदायित्व के लेने से मिनिस्ट्री स्टील की आई है, उस से बड़ी आशा बंधती है और ऐसा अनुमान होता है कि कुछ न कुछ उत्पादन की दिशा में और पार्टीसिपेशन की दिशा में संतोषजनक कार्य हो सकेगा।

मालवीय जी लेबर को भी अच्छी तरह से जानते हैं और ट्रेड यूनियन्स को और उन के विचारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे अच्छी तरह से समन्वित कर के एक पैकेज डील बनाएं क्योंकि पब्लिक सैक्टर में बड़ा कैपिटल लगा हुआ है और उस में बहुत सी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। तो एक पैकेज डील लेबर यूनियनों के साथ हो और पांच वर्ष के लिए एक इन्डस्ट्रियल ट्रूस हमें, जिस में कोई हड़ताल या तालाबन्दी की बात न हो क्योंकि अभी जो कभी हड़तालों की बात होती है या कहीं वेजेज की और कहीं बोनस की बात होती है, तो वह न हो और उत्पादन में बाधा न पड़े। कभी कोई बात होती है और कभी कोई बात होती है जिसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन से जिस का सम्बन्ध है और बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए हमारा उत्तरदायित्व है, सरकार देश का निर्माण करना चाहती है, एक विशेष सिद्धान्त की ओर अग्रसर होना चाहती है, तो उस के रास्ते में बाधा पैदा होती है।

मैं समझता हूं कि लेबर जो कि हमारे जीवन का बहुत भारी महत्वपूर्ण अंग है, उसके अधिकारों को सुरक्षा देते हुए उस में सेंस आफ पार्टिसिपेशन इनकलकेट कर दिया जाए और उसको यह अनुभव करा दीजिए कि हमारे ये प्रतिष्ठान, जिन को पंडित जी माडल टैम्पिल्स कहा करते थे, ये हमारे हैं और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं में ट्रेड यूनियन के माध्यम से यह इनकलकेट कर दीजिए कि वे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस में उत्पादन को आंच पहुंचे। इसलिए उनके पार्टीसिपेशन को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसा डील पांच वर्ष के लिए हो जाए जिस का अनुकरण प्राइवेट सेक्टर में भी हो ताकि यह जो हमारा ट्राजीशनल पीरियड एकोनामिक क्राइसिस का चल रहा है और एक साइकोसिस आफ स्केयरसिटी से हम गुजर रहे हैं, चीजों का अभाव है, कोई चीज मिलती नहीं है जिस से देश का निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है और जिस से पंचवर्षीय योजना पूरी करनी है, उसको हम पार करलें। जो बेसिक मेटीरियल्स हैं, जैसे कि लोहा है, सीमेंट है, बिजली है या कोयला है, वह हमें बिना बाधा के प्राप्त हो, तो उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है।

मालवीय जी ट्रेड यूनियन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन की विचारधारा को जानते हैं और उस को समन्वित करना भी जानते हैं और उन का प्रभाव भी है यानि जो

[श्री राम सहाय पांडे]

सी० पी० आई० की विचारधारा है उस का मालवीय जी सिद्धान्त के रूप में, दर्शन के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं। वे उसको अच्छी तरह से समझते हैं, और समझा भी सकते हैं। ट्रेड यूनियनों के माध्यम से उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और हड़ताल को कैसे बन्द किया जाए, यह मालवीय जी अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से ट्रेड यूनियनों का सहयोग ले कर और मजदूरों को एक साथ ले कर अगर तालमेल किया जाएगा तो अच्छे परिणाम निकलेंगे।

दूसरी बात यह है कि स्टील के सम्बन्ध में तरह तरह की भ्रान्तियां हैं और इस में बड़ा भ्रष्टाचार है। एकोनामिक्स का सिम्पिल प्रिंसपिल है कि डिमान्ड और सप्लाई में जो अन्तर होता है उस में जब गैप होता है, तो ब्लैक मार्केट होता है और सब कुछ होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टील के यूनिट्स हैं उन सब में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एकाउंटेबिलिटी आप जनरल मैनेजर पर रखिये और उस का सब आर्गेनाइजेशन भी उसके पास होना चाहिए। अब तो आप की जो जे० पी० सी० बनी हुई है, वह कलकत्ता में है और प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है। कलकत्ते में वह उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उस में कुछ यजमं का चक्कर है। किसी को मिलता है और किसी को मिलता नहीं है। जिस के नाम से एलाटमेंट होता है उस को वह मिलता नहीं है और दूसरे ही उस को ले जाते हैं। इस तरह से सप्लाई में बड़ा करप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि मालवीय इन सब बातों को देखते हुए लेबर को सहयोग ले कर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope you have read the Bill.

श्री राम सहाय पांडेय : मैंने यह जो आप ने तीन साल का टेक-ओवर का एक्सटेंशन चाहा है, इस को दे दिया जाए इसमें हमें कोई एतराज नहीं है आप तीन साल का एक्सटेंशन चाहते हैं, आप ले लीजिए और इस के सेन्टर में मैंने यह बात कही है और उस आधार से मैंने यह कह दिया।

स्टील प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीसिपेशन और उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे जो बात कहनी थी, वे मैंने कह दी है।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी बिल आया है तीन साल का एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए, इस को पढ़ कर मैं जरा संशय में पड़ गया क्योंकि इसकी क्लाज (3) में लिखा हुआ है

"Provided that if the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the undertaking of the company should continue to vest in the Central Government after the expiry of the period of five years aforesaid, it may, from time to time, issue directions for such continuance for such further period not exceeding two years at a time, as may be specified in the directions, so, howevere, that the total period of such continuance, including the period of five years aforesaid, shall not exceed ten years"

मेरा ऐसा कहना है कि आप इस कम्पनी को पूरा लेना चाहते हैं या इसका राष्ट्रीयकरण चाहते हैं या फिर उस कम्पनी को वापस देना चाहते हैं। इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा समझेन्स होता है कि आप इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते हैं। और दस साल के बाद वापस देना चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो शेयरहोल्डर्स क्या करेंगे और कर्मचारी के मन में यह बात उत्पन्न होती है कि दस साल तक काम करने के बाद क्या होगा। आप तीन साल तक कैपिटल को रखेंगे और उस के बाद कैपिटल का क्या करेंगे। इस तरह से कर्मचारियों में जो काम करने का उत्साह होता है, वह खत्म हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको कम से कम यह बताना चाहिए इस हाउस को कि वे इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं या नहीं। अगर दस साल के

बाद श्राप इसको वापस करना चाहते हैं तो यह बहुत इनजूरियस होगा श्रौर दस साल बाद इस को वापस देना ठीक नहीं होगा ।

सैक्शन 4 ए(1) में श्रापने कहा है कि एक चैयरमैन होगा श्रौर चार से कम नहीं श्रौर चौदह से ज्यादा मैम्बर नहीं होंगे । मेरी समझ में यह नहीं श्राया है कि श्रापने चार श्रौर चौदह क्यों रखा है, पांच श्रौर चौदह क्यों नहीं या छ श्रौर 13 क्यों नहीं । फिर श्रापने कहा है कि चैयरमैन श्रौर बोर्ड श्राफ मैनेजमेंट दूसरी रेग्लेशन श्राफ गवर्नमेंट श्राफिस हासिल करेंगे । यह बहुत एम्बिगुश्रस है । मीटिंग एटैंड करने के लिए जो उनको एलाऊंस मिलेगा वह भी श्रापने स्पेसिफाई नहीं किया है । फिर श्राप कहते हैं कि होल टाइम मैम्बर जो होंगे उनकी संख्या श्राप स्पेसिफाई करेंगे । इसका मतलब है श्राप मनमानी करेंगे जिनको मन में श्राएगा होल टाइम बना देंगे श्रौर जिन के बारे में नहीं श्राएगा नहीं बनाएंगे । फिर यह भी साफ नहीं है कि चैयरमैन या मैम्बर कौन होंगे ? ऐसा भी बहुधा देखा गया है कि जो इलैक्शन में हार जाते हैं उनको चैयरमैन वगैरह बना दिया जाता है । एक्सपर्ट श्रादमियों को श्राप रखेंगे या पोलिटिकल श्रादमियों को श्राप रखेंगे इस सब के बारे में इस बिल में कुछ भी नहीं है । केवल मात्र यह कह दिया गया है कि चार से चौदह होंगे श्रौर ड्यूटीज वगैरह उनकी क्या होंगी इसको श्राप तय कर देंगे ।

श्रागे श्राप ने कहा है कि बोर्ड श्राफ मैनेजमेंट कब श्रौर कहां मीट करे इसका फैसला वह स्वयं करेगा । श्रब मीटिंग कहां होंगी कुछ पता नहीं है । कितनी इंटरवल के बाद होंगी कुछ पता नहीं है । कहीं भी कुछ भी डेफिनिट नहीं है । पता नहीं किस फरटाइल दिमाग की यह उपज है । इस तरह की बातें तो किसी कानून में देखने को नहीं मिली है ।

डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील का होता है वह भी बहुत गलत होता है । इनकी पालिसी के बारे में श्री कछवाय ने एक सवाल पूछा था । उसके उत्तर में बताया गया कि हमने पालिसी को बदल दिया है श्रौर जिन लोगों से पैसा लिया भी गया था वह उनको वापिस कर दिया जाएगा कोश्रोप्रेटिव सोसाइटीज ने भी श्रापके पास तीन साल पहले पैसा जमा कराया था । उनको श्रब श्राप तीन साल के बाद पैसा लौटा देंगे । श्रगर लौटाना ही था तो इतने सालों तक श्रापने क्यों पैसे को श्रपने पास रख छोड़ा ?

जो मशीन श्राप बेचते हैं देखा गया है कि वह मशीन नहीं होता है बल्कि स्टील होता है । इसमें बड़ा घपला है घाटा होता है । तीन करोड़ का स्टील मशीन कह कर भिलाई में एमएसएम वालों को बेच दिया गया था एक करोड़ से इस पर हम लोगों ने हल्ला किया था श्रौर कहा था कि स्टील मशीन के स्थान पर दिया जा रहा है । लेकिन श्रापने उस श्रोर ध्यान नहीं दिया । श्रापने यहाँ कहा कि स्पेसिफिक रूल बनाएंगे तो उस श्रोर ध्यान दिया जाएगा ।

श्रापने यह भी नहीं बताया है कि जब से कम्पनी श्रापने श्रपने हाथ में ली है तब से घाटा ही घाटा हो रहा है या नफा भी हो रहा है । फर्स्ट फेज में श्राप 13 करोड़ रु० या इसमें इनवैस्ट करने वाले हैं । लेकिन यह तो पता चलना चाहिए कि इसमें घाटा हो रहा है या नफा हो रहा है कस्टोडियन और मैनेजर बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ा है यह तो पता चलना चाहिए । वहां एक भट्ठी भी जल गई थी । इस तरह की दुर्घटनाएं न हों इस श्रोर भी श्रापको ध्यान देना चाहिए ।

इनके श्रालावा में झगड़े भी चलते हैं, श्रापस में रस्साकशी भी चलती है । मंत्री महोदय कहते हैं कि मिनी स्टील प्लांट लगाएंगे लेकिन इनका स्टील का डील करने वाला जो सेक्रेटरी है वह कहते है कि मिनी प्लान्ट नहीं लगाएंगे । पता नहीं मिनिस्टर राज करना है या ब्यूरोक्रेसी राज करती है ।——

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bade, these are much larger questions You are going much beyond the scope of

[Mr. Deputy-Speaker]

the Bill, going into the setting up of mini steel plants, scrap iron, policy of Steel administration and all that. This is only asking whether you agree or not to extend the time of the takeover of the management of IISCO.

SHRI R. V. BADE: The Secretary says one policy and the Minister says another policy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As far as I am concerned, what the Minister says counts. I do not take into consideration what the Secretary says to the Minister.

SHRI R. V. BADE: Whether the Secretary rules or the Minister rules, I do not know. I do not oppose the Bill. But if you want to nationalise it, you nationalise it just now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is a very valid question that you put right at the beginning.

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYIA (Giridih): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will not take much time. I have only a few points to make.

Out of four blast furnaces there, three blast furnaces as also coke ovens are in various degrees of disrepair. The material handling requires to be much desired. The blue-prints of the designs of the plant are, I understand, missing. So, the success of our Minister will be measured by to what extent he can increase the capacity utilisation in the coming months. Production has to increase. IISCO had a very high capacity utilisation. But, unfortunately, it has gone down during the last 30 or 36 months.

The question of labour participation in the management does not end by merely putting one labour representative in the Board of Management. It has to go down to the shop level, to the formation of works committees If the workers' initiative and suggestions are taken into consideration, I am quite confident that things will improve for the better.

A question was raised by the hon. Member from the Opposition about the sale by auction of scrap materials. The difficulty has been that when the auction is on, a ring of auction purchasers gets rapidly formed and there have been cases where the prices are unduly depressed and the Company makes a loss or, in some case, the prices soar up so high that the purchasers do not take delivery. So, the best way out of the situation would be negotiated sale by tenders, in small lots but it should be by tender. That is how the vicious ring can be broken and the plant can make profits.

14 00 hrs.

Another point was made about doing away with the contract labour. I yield to none in this House as regards the elimination of contract labour. 30 years ago, I had to pay for this issue by facing an attempt at murder at the hands of contractors, by having two fractured fingres and all that. But, in the circumstances, if you want to do away with contract labour, you will be faced immediately with the issue of having to absorb 13,000 to 14,000 workers who are working under the contractors in the plant and in the captive collieries In the context of the present situation. I should think that, for a year on 18 months, this system should be allowed to continue, and the main strategy should be to make the plant increase its production. That is the crux of the matter. For that, a large amount of autonomy and discretion has to be given to the local management. Already SAIL has become a leviathon and centralisation will not make for initiative at the local level. It is only initiative at the local level which can turn the corner, which can turn the situation for the better, in the Indian Iron & Steel Company.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the scope of this Bill is a restricted one, dealing with only the aspect of take-over of the management. Therefore, I will restrict my observations only to those aspects which are related to the Bill.

At the very outset, my major criticism of the Bill would be that the entire approach of the Government in the aspect of take-over has been a fire-brigade approach, a halting approach, a piecemeal approach. In the Statement of Objects and Reasons of the Bill it has been stated that, on 14th July, 1972, initially, the management was taken over only for a period of two years. Now they have felt it necessary to extend the period by three years In fact, when they adopted the original Bill, it should have been clear to them, taking into account the complexities of the problem of management, that it was not possible, even with the best of intentions, to restructure the enire management in the course of two years. Our hon. Minister is well versed with the problems relating to management of steel industry, and even with the experience of other plants in this sector, it should have been extremely clear that, even if we were not to take up the problem of complete nationalisation but only the restricted problem of taking over of management for re-structuring, even that restricted task could not be fulfilled in the course of two years. When they found that something was wrong, without any farsightendness, they jumped into the situation and there again they did not show the farsightendness, thye did not realise that, for restructuring the entire management, two years would not be adequate. Therefore, they have a Bill, a partial Bill, only the period fixed is three years. Again they have realised that it cannot be done. Therefore a new Bill has come up. I, therefore, warn the Government that after the completion of three years—of course, they have put a little elbow room and they can extend beyond that—unless they are able to deal with the basic problems, even with the type of new management they are envisaging in this Bill they will not be able to tackle the administrative problems of the steel industry.

Here, they have suggested that they would like to restructive the entire management. Restructuring the management basically means making the Board of Management more effective in terms of two or three important aspects. The first is improving the profitability of the steel industry Then, improving its administrative efficiency and also ensuring that the interests of the consumers and labour are safeguarded by the restructured management which they are undertaking under the new Bill.

There are certain aspects of management which cannot be the subject matter of this Bill. I am quite aware of that. In fact, on some other occasion, when I was dealing with the discussion on the Company Law Amendment Bill, I pointed out to you that when certain aspects of the principal Act were not touched at all, then it will be very difficult to suggest something which goes beyond the principal Act Here again, the same difficulty arises. No doubt, it has suggested a certain structure of management, that there shall be a Board of management consisting of a Chairman and not less than 4 and not more than 14 members. I expect that the Minister, while replying to the debate, will make his opinion quite clear that in selecting the members for the Board of Management, due regard will be shown for the interests of the labour, the interests of the consumers and the interests of expertise for building up a better administrative structure for the entire steel plant. If that explanation is forthcoming, at least to some extent, I will be satisfied. And knowing the hon Minister well, I am sure he is quite conscious of these administrative tasks before the management and if they are attended to,

[Prof. Madhu Dandavate]

then probably even within the frame-work of this Bill, this restricted basic task can be achieved.

There is one more aspect which is related to the Bill and a brief mention of it is very necessary. The Administrative Reforms Commission has gone into the problems of management in depth. They have gone into the problem of the personnel policy and they had suggested that no matter whatever be the structure of the Board of Management, if an adequate personnel policy, if a sound personnel policy is not built up, in that case, with the best of intentions and with the best structure of the Board of Management, if you keep the personnel policy as it is, even the entire restructuring the Board of Management is likely to produce results which will not be commensurate with the objectives with which the revision and restructuring of the Board of Management is being brought about. Therefore, I would like to suggest that while restructuring the entire Board of Management—the minimum and the maximum number is also fixed—I think due regard will be paid to having a proper personnel policy. Unfortunately, an opinion is being built up in the public sector industry in this country and it is taken for granted, that the public corporantions are to be manned by certain officers. It is taken for granted that the IAS service probably provides the best available personnel. I have nothing against the IAS. I have nothing against the ICS officers. I would say that an IAS officer may be the mos. intelligent officer. After all, building up an industry like the steel industry, is basically a problem of expertise and dealing with the business aspects. Therefore, only because an IAS officer is an intelligent officer, you cannot take it for granted that he will be able to deal with the administrative problems and that he will be having the business acumen for the running of an industry. Therefore, it is necessary that we do not rely merely on the outdated frame of the IAS officers and we try to put premium on the expertise knowledge and competence to run the industry in an efficient manner. Keeping these norms in view if the reconstitution of the Board of management is made it will be possible for hon. Minister to tackle the problem on proper footing.

There is one thing which I would mention which although not directly related would affect what is happening in the management of the industry. This is regarding the distribution problem about which references have been made many times and this is not within the purview of this Bill. It is related in this way that with the best of management, if even productivity is improved and so on, but if the distributionship or distribution machinery is not properly manned, it will not be possible to achieve the desired results. Just taking an illustration, in a State like Maharashtra, in Bombay, forty per cent of the steel quota is sold in black-market. The CBI undertook certain investigations. Big companies like J K Company, Khira and Hyco Stone were involved. Certain quotas were cancelled. There is lot of malpractice which is taking place. This aspect should be borne in mind and rectified. If that is done, I think the situation will improve a lot. I do not think the restrictive approach of the Bill will solve the problem. But it is a step which is a welcome step. At some stage you will find you will not be satisfied with mere taking over the management but you will have to embark upon nationalisation. I do not take any doctrinaire attitude saying, socialism is identified with nationalisation. I feel that if the commanding heights of economy are to be controlled certain sectors of economy like steel have to be controlled in the national interest and in those sectors nationalisation will have to be achieved. If the steel industry succeeds in its endeavour to increase production and if surpluses are generated that will be ploughed back for further expansion and all these things can be utilis-

ed in the interest of the community at large and therefore even without taking any doctrinaire approach I do feel that in vital sectors like the steel industry nationalisation of industry becomes a must. Therefore, though I welcome, by and large, the Bill which has been moved by the hon. Minister, I would feel, the time will come when he will have to go beyond the scope of the Bill and effect complete nationalisation of this branch of industry. Thank you.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. D. MALAVIYA): I am thankful to hon. Members for having made very constructive suggestions and my presumption ought to be that there has been a general support, although conditional in certain aspects, with the Bill that is before the House for its approval. Before coming to the various points which were very relevantly or sometimes not very irrelevantly raised, I would like to give a brief background of the situation in the Burnpur Steel plant which is shown as IISCO. The Steel works at Burnpur commenced production in 1922.

It started with an operating capacity of 300 thousand tonnes till 1953 and then after the plant successfully increased its rated capacity to 500 thousand tonnes and thereafter.

It produced a million tonnes of ingots with the salable steel production of the order of 800 thousand tonnes. At that time the company had a very good record; the machinery was new and so it started well. Many of the evils that crept in later on were not there at that time. But, then the deterioration started taking place rather rapidly and, as against the rated capacity of one million tonnes, the production which was very good in 1963-64 fell down to about 600 thousand tonnes. The actual production of salable sent during April 1972 was 34,500 tonnes and it reached in June an all time low record of 23,000 tonnes.

Thus, the House will see that there was a rapidly deteriorating condition of the plant and when this Report was made available to the Government it appeared to all of us that this deterioration was the direct result of ineffectiveness that should have been there. The attitude of the management too was unresponsive to the grave and very urgent problems which needed attention. A rehabilitation programme was also very necessary at that time because the plant was getting old as it was almost about 45 years old. So, the rehabilitation was needed. Capital was not there. And nobody bothered about investing money. Everybody at that time wanted to make money out of it. Therefore, rehabilitation was very gravely neglected.

Therefore, it was considered appropriate that the plant which was doing very well only a few years back should not be allowed to deteriorate further. Because of the all-time low record of production in the month of June 1972, it was considered appropriate that the management of the company should be taken over. The management of it was taken over for a period of two years. It was taken over on 14th July, 1972 by an Ordinance which was later on replaced by an enactment.

At that time, let me submit that the object of the take-over was to give better professional and broad-based management which was not there. There was no professional aspect involved. The people were more interested in the general aspect of setting up of a plant and then making money out of it. Government had the intention of completely re-orienting the structure of the management to which I shall come just now. The Government had the social objectives before them and then to make a programmed investment, if I may use that word, with a view to making this position satisfactory so that the social ends and the economic ends which the Government had may be fulfilled. Some steps were therefore hurriedly taken about which I need not go into in greater details. The Engineering and Development Division of the IISCO prepared that scheme towards

[Shri K. D. Malaviya]

the end of 1971. At that time perhaps the scheme was drawn up at an estimated cost of about Rs. 21 crores.

The scheme was approved by the then Board of Directors but later on as Government took over by that time the situation changed and after the take-over of the management of the Company, the scheme was thoroughly re-examined and revised. According to the revised estimates prepared in September, 1972 the cost was estimated at Rs. 45.90 crores with a foreign exchange content of Rs. 4.04 crores. In view of the sharp increase in cost, the scheme was remitted to a group of technical experts as a result of which a revised scheme with slight modifications at a cost of Rs. 43 crores was approved. Upto the end of June, 1974 an expenditure of Rs. 16.86 crores had been incurred on the scheme and the committed expenditure as on that date was Rs. 29.21 crores. The essential features of the Plant Rehabilitation Scheme are: (a) Improvement of raw material handling facilities particularly in relation to coal and iron ore; (b) Emergency and hot repairs of Nos. 7, 8 and 9 Coke Oven Batteries and re-building of No. 7 battery which was completely out of order, etc. etc.

I may also mention there has been some set-back in the actual implementation of the Plan Rehabilitation Programme. It is expected that that Steel Plant will now be able to reach its rated capacity by 1976-77 after the completion of the Plant Rehabilitation Programme.

Sir, the cranes and the ground chargers were in a bad state when we took over. Much headway could not be made in the beginning. This work of improvement and rehabilitation of cranes was awarded in August 1973 to Jessops, a public sector undertaking. One set of cranes and ground chargers have already been made available and installed and the balance work is expected to be completed in about 15 months' time.

Before I come to production and distribution I would like to make one or two points. The first point was raised by Mr. Limaye which was followed by Mr. Chatterjee and just now by Mr. Dandavate as to why do we take piecemeal method of trying to improve one of the basic industries in the country like Steel Industry. I might express my views about it. When it was taken over in the year 1972—if I may use the word—it was a penal action. It was not a decision to nationalise the industry from a policy angle so much as it was considered the situation has deteriorated to such a dangerous level that the action was a more of the nature of a panel action than an ideological one.

श्री मधु लिमये : ठीक ठाक करके वापिस देने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : उस पर भी मैं आता हूं, थोड़ा सा धीरज रखिये ।

श्री मधु लिमये . बहुत धीरज है मुझे, और मैंने जिन्दगी में किया गया है ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: A commitment was made by him that the intention was to return the management of the company; not to the old management. That commitment was made. I do not know whether the Minister is aware of it.

SHRI K. D. MALAVIYA: I do not know. That commitment is not before me. I will make sure, as to what the commitment was. I am only giving my considered view, from the Ministry's point of view.

PROF. MADHU DANDAVATE: I would like to seek one clarification. We would expect that after treating these plants as sick plants and improving their health in our government hospitals at our cost, are you going to give the "improved patients" to the same private entrepreneurs? We want a categorical reply on this.

श्री के० डी० मालवीय : गवर्नमेन्ट का इतना रुपया लगने और बुराइयां दूर करने के बाद वापिस देने की बात नहीं है। लेकिन यह ऐसे मामले होते हैं जिनपर बहस नहीं की जाती है। मैं शासन के साथ आपका सहयोग चाहता हूं। आपको उसकी जानकारी हो, मैं समझता हूं हमसे कम जानकारी आपको नहीं है बल्कि ज्यादा है तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना रुपया लगाने के बाद और बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के बाद अगर हम इस कारखाने को फिर वापिस कर दें, जिन से कि सरकार ने उस को लिया था--किसी भी मुनासिब वजह से या उनकी गलतियों के कारण लिया था--तो कोई बद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। लेकिन इस समय यह क्यों पूछा जाता है कि आप की नेशनलाइजेशन पालिसी क्या है। कमांडिंग हाइट्स देने की यह तमाम बातें तो हैं ही, हाउस को सब मालूम है क्या हुआ है।

But, when a plant is brought to a satisfactory level of efficiency and when it goes into operation in a satisfactory manner, looking into the social objectives that we have before us,—what the socio-objectives are can be looked at from an elastic point of view or a pragmatic point of view or a strictly philosophical point of view: I do not want to introduce those aspects—the fact is that when a society has laboured so hard and invested so much money in it and has brought this up to a satisfactory position, personally, I do not think there can ever be a question of handing it over to those people who were found guilty of destroying public property.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why should it be for two years and three years?

श्री के० डी० मालवीय : मैं तो नहीं जानता कि सन् 1972 में दो साल के लिए जब यह ली गई थी तो उस की कौन सी वजहें थीं वह तो कागज की देखभाल करने पर पता चल सकता है लेकिन दस साल की जो अवधि दी गई है वह सभी चीजों की देखभाल कर के किया गया है कि दस साल के अन्दर सारी चीजें सम्भल जायेंगी, एक्सपैंशन भी हो सकता है और यह सब काम मुनासिब तौर से हाथ में लिया जा सकता है।

मधु लिमये जी ने कुछ स्कैप के बारे में और डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में भी कहा है, मैं पहले उसी के बारे में बता दूं। इसको या जो

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why do you switch over to Hindi?

SHRI K. D. MALAVIYA: I got inspired by my friend Mr. MADHU Limaye.

MR DEPUTY-SPEAKER: To make the whole thing more philosophical so that the Chair may not exactly catch up with what he says!

SHRI K. D. MALAVIYA: Before the take-over of the management of IISCO, the scrap that was produced there was sold through negotiated deals, which was very unsatisfactory, and which had so many loopholes. This should not have been done. But, after the take-over, a system of public auction was introduced. In my opinion, even the system of wholesale public auction, sometimes, in such matters, should not be considered desirable and proper. There are few people who bid in this auction. Sometimes, they conspire among themselves and they quote, under-quote in such a manner that it becomes difficult for us to find out any other alternative. Therefore, Government then considered that there should be something in between or a mixture of the things, and felt that some hard and more rigid rules should be made, but that is still to come.

Two auctions with wide publicity on an all-India level were held during the last one year and they fetched a higher price, and for that my hon friend Shri Somnath Chatterjee . . .

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): Higher than what?

SHRI K. D. MALAVIYA: For that, my hon. friend Shri Somnath Chatterjee gave the whole credit to Mr. Ray. I do not wish to dispute it . . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I did not say that; I only said that during his management this was done, and I believe that the hon. Minister himself has admitted that in the other place.

SHRI MADHU LIMAYE: Higher than what?

PROF. MADHU DANDAVATE: Higher than the lower one!

SHRI K. D. MALAVIYA: Yes, higher than the lower one. What happened at that time was this. During the last two years . . .

PROF. MADHU DANDAVATE: Let him give a specific reply?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I do not minimise his contribution. I am not saying that he must get all the credit for whatever has been achieved; I have never said that.

SHRI K. D. MALAVIYA: I am only trying to submit some facts of the situation that existed.

SHRI MADHU LIMAYE: Higher in relation to what? Let him be specific.

SHRI K. D. MALAVIYA: The price of scrap went so high, as compared to what it was two years back . . .

श्री मधु लिमये : मेरा सवाल है कि किस से हायर थी ?

SHRI K. D. MALAVIYA: . . . . that the revenue out of the sale or auction of the scrap was naturally quite high, as was indicated by my hon. friend Shri Somnath Chatterjee.

श्री मधु लिमये : हुजूर, दो साल पहले कहां ऑक्शन होता था ? पुराने स्क्रैप डील्स को आप ने जांच के लिये भेजा है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं ।

श्री मधु लिमये : खुद आप कह रहे हैं कि 50,60 लाख रु० ज्यादा मिला इन दो ऑक्शन्स में ? प्राइस इन्क्रीज के लिये भी आप अलाउन्स कीजिये, फिर भी जो पुराने निगोशियेटेड सेटिलमेंट्स थे उस में पैसा खाने का काम होता था । तो उस की जांच करनी चाहिये ।

श्री के० डी० मालवीय : वह तो पहले की बात थी । टेक ओवर से पहले जो होता था वह मैं ने बता दिया आप को ।

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, please protect us on one point. He says that it was higher than what it was two years back. At that time, was there auction there? Let him reply to that.

SHRI MADHU LIMAYE: He must investigate those deals.

SHRI K. D. MALAVIYA: As against negotiated sale, I only used the word 'auction' . . .

श्री मधु लिमये पुराने डील्स का इन्वेस्टीगेशन यह करेंगे कि नहीं ?

SHRI K. D. MALAVIYA: I do not wish to give in . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall allow a few questions to be put by the hon. Member at the end. Now, let the hon. Minister go on. He has the right.

SHRI K. D. MALAVIYA: In between these two public auctions, the IISCO had sold some scrap to individual parties at the negotiated prices keeping the earlier auction prices as base. This system was also not desirable and it has been stopped. It

has also been decided that available melting scrap will first be offered to the public sector units. Now, what we are doing is that we first give it to the public sector units. And than we are selling the material to actual users, not for trade; we are trying to discourage completely the practice of people auctioning and taing it for carrying on trade. The object is first to supply it to the public sector units for their own use and then to give it to actual users....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: At what rate? Who fixes the rate?

SHRI K. D. MALAVIYA: The rates are to be decided by the actual persons there, it is not for me here to sit down and specify the rate.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: On the basis of the market rate?

SHRI K. D. MALAVIYA: If it is better than the market price we shall accept it.

Another point which was made by Shri Madhu Limaye and others was this. Scrap used to lie all around the steel plant campus at Burnpur which provided opportunities to undesirable elements to go and take it There were complaints of pilferages of the steel item along with scrap which was lifted by the buyers. There were many kinds of things happening there. It was a bad legacy, and there were many undesirable elements and many bad practices there, which had crept into the whole plant. It tooks some time in our own pattern of socialist management and the manner in which we are dealing with problem of law and order, of restraining all these undesirable things and so on; it really took some time for Mr. Ray to control the situation and to settle things and bring the whole system under control.

Now a scrap yard has been established and future pilferage will stop. Scrap will now not lie scattered here and there. I personally went and saw the arrangements. These things were getting collected in the scrap yard under construction. This stockyard will help in seggregating the scrap quality-wise making it possible to secure higher prices and also safeguarding against pilferages.

Coming to contract labour, my hon. friend knows that under the earlier management recruitment was a spoil-system, but there was not a very bad practice that 50 per cent of the vacancies created were reserved more or less for the wards or children of the existing employees. It did give an emotional attachment to the plant....

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): A sense of belonging.

SHRI K. D. MALAVIYA: As my hon. colleague says, it gave a sense of belonging.

Then some serious complaints started coming in and after the takeover the recruitment system was rationalised. It has also been decided that the new recruitment will be effected in association with the Employment Exchange. A consultative system is now being developed with a view to see that our recruitment policy is on healthy and proper lines.

PROF. MADHU DANDAVATE: What will happen to contract labour?

SHRI K D. MALAVIYA: We are never in favour of it. But even the Joint Negotiating Committee of workers have conceded that in certain spheres, the contract labour system can be removed only gradually. Whether it is steel or coal, they have accepted that it should go as soon as possible. The Governmeint agrees with that vie w that it should go as soon as possible.

SHRI MADHU LIMAYE: Have a time-bound programme.

SHRI K. D. MALAVIYA: But there are certain specialised plants where we have got to close our eyes to certain irregularities and injustices because we want to proceed ahead in order to abolish it.

The House knows that immediately this Bill came before the Rajya Sabha, automatically the services of Mr. Ray were terminated, because it ended there and a new small nucleas board of management has been created with Mr. Bhayya as Chairman. Mr. Bhayya is not an IAS man. There is no speciality of IAS men to occupy the top positions in these bodies or institutions everywhere. It is not there. When we bring an efficient officer from outside, whether from Tatas or others, then objections are raised We have brought one of the most efficient officers and Shri Chatterjee, if I may be allowed to say so, was not justified in attacking him in the manner he did yesterday, I do hold that after a little experience, the concept of holding companies may require marginal or peripheral adjustment.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You allow sufficient time for the Chairman of SAIL because he comes from the Tata group. Therefore, he can have whatever time he wants

SHRI K D. MALAVIYA: To attack a person because he has come from the Tatas is something I consider highly undesirable.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You have not fairly treated one who was inducted into this company by the late Steel Minister, who made some sacrifices and knew that these two years were allowed to him. You are allowing an unlimited time to the other person who has come from the Tata group to establish himelf

SHRI K. D. MALAVIYA: If he wants to raise the question of Mr. Ray, I have nothing to say and no comments to offer except that he know in what manner dog fights were going on between these so-called experienced people. My object was to stop this. A man who had come down from times immemorial from IISCO was there and Mr. Ray was also there. We decided that both of them remaining there was not in the interest of the concern. Therefore, was had naturally to smoothen it So, a new set-up was created. IISCO was taken over for a further extended period. Under the new arrangement, Mr. Bhaya was asked and he readily agreed to become the part-time Chairman. We have still to complete the list. Some criticism was made, as to why it should be 14 It all depends upon how many people are required to complete the board of management. We may require only 7 and 9 people. So, far 6 people have been appointed, presided over by Mr Bhaya Mr. Gopeswar is the trade union representative there who was the first man to be selected Mr Gopeswar is very well known in IISCO not only among the INTUC but also CPI, HMS and Marxist organisation Now they are functioning normally and the relations are amicable They all individually and jointly met me and said, everything is all right.

MR DEPUTY-SPEAKER. We have a well-established practice not to discuss individual officers

SHRI K. D. MALAVIYA: Yesterday so much was said about it and inter-union rivalry is there. Therefore, I thought I should clarify the issue that there is not much trouble about the specific selection Labour has been given representation. There is a Chartered Accountant, Mr. Dastur is there as the representative of that engineering institution One of them is, of course, an IAS officer, who represents our Ministry, Mr. Sidhu and Mr Banerjee is there, who is the Technical Director of SAIL, to look after the technical interests.

A suggestion was made that all problems of sales, distribution and production should be integrated at one

point. It is not a very practical solution. The Ministry takes care of the problems that are involved in production and distribution. There has to be a division of work. The distribution has been organised and it is going to be streamlined further. There is nothing wrong about it. They are aware that there is a system of allocation of steel. Mr. Dandavate said, about 40 per cent of the steel was selling in the black market. I am not aware of it. It is true that when steel is allocated to specific authorities including the State authorities, a part of it is not traceable. It is our effort and it will continue to be our effort to improve the distribution system. Many people have been arrested and sent to jail. Our job is only to pinpoint the distribution and some other authorities take care of it. It is our constant desire to improve the distribution system. There is the steel priority committee. It is not entirely controlled by the Steel Ministry. The Secretaries of various economic Ministries get together and allot priorities In this manner about 80 per cent of the steel goes to priority sections like Defence, Public Sector industries and also State Governments We have always emphasised with the State Governments that the steel allocated for a specific job should go only for that purpose. Sometimes it does not. So, I entirely agree with the sentiments of the House and it will be our constant efforts to improve the distribution system because here and there we do find omissions which ought not to remain.

I have already spoken about the induction of technical elements into our Secretariat. The hon. House is already aware that so far as coal is concerned, we have got a Secretary, who is not a bureaucrat. He is one of the top-most engineers in the country Similarly, we have got a Secretary in Steel who has got the best experience of business dealings and distribution, who can grasp the matter much more quickly in a business like way than a bureaucrat. Therefore, I am not giving a good chit or a bad chit to any man. All that I am saying is that we are deviating from the old rut and we are introducing a new system of injecting new elements into the entire system of functioning.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why Dr. Bhattacharyya was removed from Bokaro? Why this sudden change?

SHRI K D. MALAVIYA: In such matters some latitude has to be given to the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I draw the attention of both the Minister and the Members that I think we have widened the scope of this discussion to cover the entire gamut of steel administration. It is interesting to hear the Minister. But, then, we get into discussion of personnalities why this officer has been removed, why that officer has not been removed, why this officer has been given preference over that officer, and we get into all kinds of difficulties.

SHRI K D. MALAVIYA: Personally, I would not like to support or defend any individual officer in the Ministry. But yesterday a very strong point was made by my hon. friend and I thought I should reply to that.

I feel that we should not be criticised for making changes whenever we consider them necessary in the interest of the functioning of the Ministry. If my hon. friend has any specific point to make, he can come to me and make enquiries. I am always available to him.

PROF. MADHU DANDAVATE: There is no personnel policy.

SHRI K. D. MALAVIYA: It is very much there. There is a Personnel Officer If there is any specific scheme which the hon. Member can produce, with regard to improving the personnel policy, we will consider it. We have got a personnel policy. We select people through a Selection Committee and then we give them train-

[Shri K. D. Malaviya]

ing. We do not just pick up a man because a man likes him or another man does not like him. That is not so. Even giving employment to the local people is very much before us. Sometimes we do find that the local people down below are neglected and then we take special care to see that local people are employed. In fact. we give them preferenee even when we find that they are a little below the mark

There are one or two amendments given notice of by Sardar Swaran Singh Sokhi. I do not propose to accept them because they are not very relevant. For instance he wants to change from five to four years It can be asked why not six years.

MR DEPUTY-SPEAKER· He has not even moved them

श्री के० डी० मालवीय : मुझे जो अमेंडमेंट के सम्बन्ध में कहना था, वह कह दिया है। अब बाद में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट में कोई बात नहीं है।

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, मैं ने मंत्री महोदय का जवाबी भाषण बहुत गौर से और प्रेमपूर्वक सुना, लेकिन मुझे इस बात को लेकर निराशा हुई कि इस सभा में सभी लोगों के द्वारा जो माग रखी गई थी कि यह कारखाना ठीक ठाक होने के बाद भविष्य में कभी भी निजी इन्तजाम के सुपुर्द नही करना चाहिए इस के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट आश्वासन नही दिया है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि हमारे कहने का उन पर असर होगा।

इस्को की कांट्रैक्ट सिस्टम का, इनकी कांट्रैक्ट प्रणाली का जो सवाल मैंने उठाया था—मुझे अफसोस है कि उस पर इन्होंने लीपा पोती ही की है। इनको स्पष्ट कहना चाहिए था कि एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे। मैं जानता हूं कि इस दूषित प्रणाली को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है या दो महीने में समाप्त नही किया जा सकता है। लेकिन कोई समयबद्ध कार्यक्रम तो ये हमारे सामने रख ही सकते थे।

श्री के० डी० मालवीय : प्रेक्टीकल नही है।

श्री मधु लिमये . प्रेक्टिकल और आयडियल व्यवहार और आदर्श दोनों में कोई समन्वय आपको करना है। आप ऐसा नही करते है। आप की नीति बड़ी दिशाहीन रहती है। एक सिद्धान्त आप प्रतिपादित कर देते है और जो आपका कर्म होता है वह उसमे कही मेल नहीं खाता है।

आकशन प्रणाली चालू करने के बाद कम्पनी का जो अनुमान था स्क्रैप डील से कि उसका इतना पैसा आएगा, पुराने अनुभव के आधार पर, उसमे दोनों आकशज में, 50—60 लाख प्रति, मिला है। श्री राय की वजह से ऐसा हुआ था और किसी वजह से इस में मैं जाना नही चाहता हू। मंत्री महोदय ने इस की वजह एक यह भी बताई है कि बीच में स्क्रैप के दाम बहुत बढ गए इसलिए ज्यादा मिला। यह अर्द्ध सत्य है और अर्द्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। दाम वृद्धि एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि जब कम्पनी निजी इनजाम में थी तो स्क्रैप डील में बहुत घपला था, इसलिये मैंने इन्दिरा जी को लिखा। प्रधान मंत्री के सामने मैं बार-बार इस बात पर जोर देता रहा, और मैने इस बारे में उनसे लिखा पढी भी की और उनका ध्यान इस ओर खीचा था। मंत्री महोदय को इस मे क्या तकलीफ होती है और पुराने स्क्रैप डील्ज मे कोई घपला हुआ है ..(**इंटरप्शंस**) घपला माने घोटाला, गड़बड़ी। इस को तो आप मानेंगे ही कि हिन्दी में शब्द अंग्रेजी की तुलना मे तीन गुना अधिक है। मैं प्रार्थना करता हू कि कम से कम पंडित जी (श्री कमलापति त्रिपाठी) हिन्दी मे ही बोला करें। असमिया

बंगला, मलयालम के भी में शब्द लेता हूं और कभी कभी वे बहुत काम के होते है बहुत बढ़िया शब्द होते हैं। जब आप ही बताइये कि "इकवी डिस्टेन्स थिअर" को आप हिन्दी मे क्या कहेगे ? समान दूरी वगैरह ही तो कहेगे ? लेकिन मलयालम वाले कहेंगे समदूर सिद्धान्त। भारत की भाषाओ की गरिमा को आप नही जानते है। टूटी-फूटी अंग्रेजी छोड दीजिये। मुह बना कर अंग्रेजी में बोलना छोड दीजिए। ऐसी हिन्दुस्तानी को आप अपनाए कि जिसमे भारत की सभी भाषाओ के अच्छे शब्दो का समावेश हो।

स्क्रैप डील के बारे मे मेरी प्रधान मत्री से लिखा पढी हो चुकी है। मत्री महादय का यह कहने मे क्या दिक्कत है कि पुराने स्क्रैप डील्ज की जाच की जाएगी और अगर उसमे चोरी हुई तो चोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी क्या पुराने लोगो के साथ कोई आपने डील किया है छिपकर के ? अगर आप यह नही करते हैं तो मतलब होगा कि उस पर आप चादर बिछाने का काम करते है। अगर इस तरह का डील नही किया है तो आप को स्पष्ट आश्वासन देने मे तकलीफ बिल्कुल नही होनी चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय : मैने यही कहा कि मुझे मालूम नही है। जब टेक ओवर किया उस से पहले किसी ने क्या किया उस मसले मे हम नही गए। यह प्रश्न हमारे सामने नही था। इस वास्ते कमिटमेंट का कोई सवाल पैदा नही होता। आप कहते है कि प्रधान मत्री के साथ आप ने लिखा पढी की है। उस का मुझे कुछ मालूम नही है। आप व्यक्तिगत तौर पर कोई सुझाव देना चाहते है तो उस पर गौर हम करेंगे।

श्री मधु लिमये : इनका मैमोरेंडम आप पढ़ें। इनको क्यों अध्यादेश जारी करना पडा ? इन्होंने कहा कि हम जब गहराई मे गए और जब पता लगा कि कितना नुकसान प्लाट को पहुंचाया गया है ....

श्री के० डी० मालवीय : निगलैक्ट एंड अदरवाइज।

श्री मधु लिमये यही तो मै कह रहा हू कि दो साल के अध्ययन के बाद यदि इन का पता चला कि इतना डैमेज हुआ है तो इन को इस मे भी जाना चाहिये था। कम्पनियो की मलाई निकालने का एक तरीका आजादी के बाद शुरू हुआ है और जिन जिन लोगो के हाथ मे ये सारे उद्योग चले गए है इन लोगों ने बड़ी तेजी से मलाई निकालने का काम किया है। जैसे डी एम एस का दूध मिलता है उसी तरह ये सारे प्लान्ट्स और कारखाने सिक बन कर रह गए है। डी एम एस के दूध की जो हालत है वही हालत इन सिक मिल्ज और कारखानो की है और इसलिए जाच आवश्यक है। आगे को अगर आप भागने देगे तो एक एक मिल और कारखाना सिक बनता चला जाएगा और आप उन को लेते जायगे। तो कहा जा कर मामला रुकेगा ? मैने शुरू मे कहा था कि आप की गलत नीतियो के कारण अच्छी कम्पनिया भी सिक हो जायगी।

मैने नेशनल रेयन कार्पोरेशन का उल्लेख किया। कोहिनूर मिल का उल्लेख किया। कार्पोरेशन का जो अव्वल नम्बर का बदमाश है चूकि वह मार्केट मे और अधिक इनवेस्ट करेगा इसलिए उन को ये दो कम्पनिया आप दे रहे है और ये भी सिक बन कर रह जायगी। (व्यवधान) आप बहुआजी मौजी और मस्त आदमी है। आप को क्या परवाह है कि अर्थ व्यवस्था का क्या होता है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इन के बस का मामला नही है।

इन्हो ने कहा कि इस्पात की पैदावार बढ़ाने के लिये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे है और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते है। इस उद्देश्य से हम सहमत है। यह भी इन्होंने कहा है कि जो इस्पात का वितरण होता है, विभिन्न प्रोडक्ट्स का होता है उस के ऊपर हम निगरानी रखना चाहते है। एड यूज,

[श्री मधु लिमये]

प्रतिम जो उस का इस्तेमाल होता है उस के ऊपर नियत्रण रखना कितना कठिन है उस की चर्चा इन्हो ने की है । यह कहा है कि कुछ इस्पात कोटा राज्यों के अधीन आते है, कुछ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिग्ज के हाथ मे रहते हैं । लेकिन क्या इस्पात मत्रालय का यह कर्तव्य नहीं है कि एड यूज के ऊपर वह कुछ न कुछ नियत्रण रखे । मैं ने एक स्पेसेफिक उदाहरण दिया है कि मारुति को अब तक जो कोटा दिया गया है, जिस को पचास हजार गाडियों का लाइसेंस मिला है, क्या नेशनल प्रायोरिटीज मे निजी, आटोमोबाइल्ज के लिए स्टील कोटा देना यह बात आ सकता है ? अगर ट्रक्स के लिये बसो के लिये कोटा दिया जाता तो मेरी समझ मे आता लेकिन उस के बारे मे आप ने जानबूझ कर चुप्पी साधी है, मौन सम्मत्ति का दर्शक भी होता है । आप के मौन का यही अर्थ निकलता है । मारुति के बारे में मैं ने जो अभियोग लगाया है कि वे काले बाजार मे इस्पात बेचते है, उस मे कुछ सत्य का अंश है

श्री के० डी० मालवीय · मारुति को लोहा मिला है । बसों के लिए मिला या नही इस से उस का सम्बन्ध नहीं है । वैयक्तिक रूप से जब मुझ से माननीय सदस्य ने पूछा तो मैं ने कहा कि जहा तक इस साल का सम्बन्ध है नौ सौ टन मारुति को लोहा अलग दिया गया है उन के काम के लिए । प्राइवेट इंडस्ट्रीज को चाहे वह चीनी का कारखाना हो, चाहे मोटर का कारखाना हो, चाहे सीमेंट का कारखाना हो, चाहे कपड़ा का कारखाना हो, सब के लिए हमारी प्रायोरिटीज के अदर जगह है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before we proceed further, I do not know how this debate started yesterday. When the Minister was speaking, I noticed that the discussion went very far out of the scope of the Bill, but I allowed him because he said that he was replying to certain specific points that were raised by Members. If these points were raised, the Minister could legitimately claim the right to reply to those charges. But, now I find that instead of discussing this Bill whose objective is very limited to extend the period of takeover by another three years. . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: and the Management.

MR. DEPUTY SPEAKER: and when the Minister has said in so many words though not directly, that it is not the intention to hand over the management back to the old management Board or whatever it is, then what is the mystery about the extension? I do not understand That is the only thing that is relevant here.

When the Minister himself has entered the field of steel allocation and all that, I do not know where I can stop Mr. Madhu Limaye I wish I could say that it should be enough and call a halt there. Otherwise, we will get into deeper waters.

श्री मधु लिमये उपाध्यक्ष महोदय, मे चौथे मुद्दे पर आया था । तीन मुद्दे मेरे क्या इस बिल से सम्बन्धित नही थे ? पहला मैं ने क्या कहा कि इस कारखाने का फिर कभी निजी क्षेत्र मे न जाने दीजिये, यह रेलीवेंट है । मैंने कांट्रैक्ट लेबर के बारे मे कहा क्योंकि इस मे मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है । वह रेलीवेंट था ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (नवादा) : उस का जवाब मिल गया आप को ।

श्री मधु लिमये : मैं आप से नहीं कह रहा हू, उपाध्यक्ष महोदय को समझा रहा हू ।

फिर इसको के स्क्रप डील के बारे मे, सरकार के मनेजमेंट मे आने के "इस्को" के बाद ज स्थिति थी उसके ऊपर मैंने कहा । अब जो मैं कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि इस्को की मांग लीजिए इस्पात की

पैदावार कुछ मात्रा में बढ़ी। तो क्या होगा ? उसका जो वितरण होगा और उस के एन्ड यूज की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि यही मंत्रालय है, अगर इसका कुछ भी नियंत्रण नहीं रहेगा, नेशनल प्रायरिटीज का जरा भी विचार नहीं किया जायगा तो जो पैदावार बढ़ने से राष्ट्र का लाभ हुआ है वह बहुत हद तक खत्म हो जायगा, इसलिए मैं कह रहा था। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन्होंने कहा कि 9 सौ टन मारुति को दिया। 900 टन तो आपके कार्यकाल में मिला है। अब मैं आपकी जानकारी के लिये केवल आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें से अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया। एन्ड यूज का सवाल इसीलिए सामने आता है कि मारुति कारखाने की बनावट पर खर्च नहीं हुआ है, तकरीबन 500 टन इसका ब्लैक में चला गया और ब्लैक में दो तीन हजार रुपये टन का मार्जिन है इसके ऊपर। मंत्री महोदय मार्केट में जा कर जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। अब 500 को आप गुणिये 2 हजार रुपये से तो क्या रकम आती है ? हमारे प्रोफेसर साहब नहीं हैं। दस लाख रुपये का मामला हो जाता है। मैं तो कम फिगर पकड़ रहा हूं 500 टन की कि इतना ब्लैक में चला गया और दो हजार प्रीमियम मिला तो दस लाख रुपये इस हिसाब से मिला। इनके पहले के जो मंत्री थे टी० ए० पाइ साहब और मोहन कुमार मंगलम साहब तो उस समय भी यह सिलसिला चलता रहा। तो मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हूं कि सरकारी कारखानों में जहां उत्पादन बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए, वहां सख्ती से एन्ड यूज के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही अपनी वरीयता का, प्रायरिटीज का भी ठीक तरह से रखना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जनता के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन बढ़ेगा। उन्हीं चीजों के लिए आपको स्टील के मामले में प्रायरिटी देनी चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं, स्काई स्क्रपर्स का मैंने सवाल उठाया और मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। केन्द्र की जमीनों की चोरी बम्बई में होती है। उसके ऊपर 2 करोड़ 80 लाख की रिश्वत ली जाती है। अब उसके ऊपर अट्टालिकाओं के लिये इनको कोटा मिलेगा। इंडस्ट्रियल डवलपमेंट मिनिस्ट्री से सीमेंट का कोटा मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : नहीं मिलेगा।

श्री मधु लिमये : नहीं मिलेगा ? क्या कह रहे हैं आप ? बिल्डर्स ने रिश्वत इसीलिए दी है कि 75–75 लाख रुपये कमायेंगे जो बिल्डिंगें बनने वाली हैं उनमें। उसमें सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक की भी बिल्डिंगें बनने वाली हैं। तो मैं केवल यही चाहता हूं कि आप जब जवाब देंगे, थर्ड रीडिंग पर या क्लाज वाइज क्लाज कंसिडरेशन पर तो स्पष्ट घोषणा कीजिए कि बम्बई के बेकबे रिक्लेमेशन के स्काई स्क्रपर्स के लिए एक किलो भी स्टील नहीं मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी यह कल्पना है, इन सब मंत्रियों की कि हमेशा मैं इनके पीछे पड़ता हूं, मैं इनको बदनाम करने का प्रयास करता हूं, लेकिन कोई मेरा दिमाग परवर्स है ? मैं देश हित की बात करता हूं। इसमें कोई परवर्सिटी की, विकृति की बात नहीं है। अगर वे अच्छा काम करेंगे, उस दिन पंडित जी ने कहा कि अब हम पार्ट ट्रस्ट एरिया की जमीन को कानून के तहत ला रहे हैं तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नींद देर से खुली तो भी अच्छा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I really admire your resourcefulness.

श्री मधु लिमये : आप ने काम्पलीमेंट से आज मुझे मारने का फैसला किया है तो मैं अब बैठ जाता हूं।

SHRI K. D. MALAVIYA: He is only provoking me to answer this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot match Mr. Madhu Limaye in all these matters. And I think the Minister would be very well advised if he keeps away from wider issues.

श्री मधु लिमये ऐसा मत करिये। इन मंत्रियों मे और मुझ मे डायलाग चल रहा है उसमें आप बाधा मत बनिये। उसको चलने दीजिये। बहुत सारे इन लोगो से, जो पुराने फ्रीडम फाइटर रहे है, जरा मेरी मुहब्बत है। इनको देख कर जरा मेरा मन भर जाता है, इसलिए आप उसमे बाधा मत बनिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is

"This House disapproves of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No 4 of 1974) promulgated by the President on the 28th June, 1974,"

The motion was negatived.

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

"That the Bill to amend the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Act, 1972, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER We go to Clause-by-clause consideration. On Clause 2 there are no amendments The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER. Clause 3 Shri Swaran Singh Sokhi--not here. The Speaker this morning made very special comment about him. I see that amendments to Clause 4 also stand in his name and another amendment to Clause 6. In that case, I think, I can put all the Clauses together to the vote of the House The question is:

"That Clause 3, Clause 4, Clause 5, Clause 6, Clauses 7 to 11 and Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble. and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3 Clause 4, Clause 5, Clause 6, Clause 7 to 11, and Clause 1, the Enacting Formula the Preamble and the Title were added to the Bill

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K D MALAVIYA): Sir, I beg to move

"That the Bill be passed"

MR DEPUTY-SPEAKER Motion moved

"That the Bill be passed"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले मे मैं तीन बातें निवेदन करना चाहता हू। वैसे श्री मधु लिमये जी ने अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए कई ऐसी बातें कही हैं जिनमे मैं भी सहमत हू। उन बातो के अलावा मैं बोर्ड ग्राफ मैनेजमेंट के सिलसिले मे कुछ कहना चाहता हू। मंत्री जी को मालूम होगा कि बोर्ड ग्राफ मैनेजमेन्ट मे ऐसे बहुत सारे लोग, अफसरान, रखे हुए है जिनकी प्रसिद्धि बहुत ही बुरी रही है, बदनाम किस्म के लोग रहे हैं। जिनके बारे मे इस सदन के अन्दर दूसरे सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी बारबार सवाल उठाये गये हैं कि ऐसे बदनाम लोगो को न रखा जाय। लेकिन फिर भी घुमा-फिरा कर उन्ही लोगो को व्यवस्थापकों मे रखा गया है जो इस कारखाने को चला रहे है। मैं ऐसे ही एक सज्जन का नाम इसलिये लेना चाहता हू कि यहा उनका नाम लिया जा चुका है—श्री निहार दत्त। इनके बारे म राज्य सभा मे भी सवाल उठाये गये . . .

श्री के० डी० मालवीय : वह चले गये हैं।

श्री रामावतार शास्त्री: अगर चले गये है तो ठीक है। क्या कारखाने के क्वार्टर मे भी चले गये हैं या अभी भी वही जमे हुए है?

श्री के० डी० मालवीय : इसके लिये मैं कुछ नही कह सकता।

श्री रामावतार शास्त्री: अगर चले गये हैं तो बडी खशी की बात है। ऐसे लोगों को जाना ही चाहिए था, क्योंकि इनके बारे मे बहुत हगामा हुआ था। इनके बारे में हमारे ही सदन के सदस्य डा० रानेन सेन ने, जो आल इण्डिया ट्रेड युनियन काग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होने भी सवाल उठाया था। हमारी ए०आइ०टी०य०सी० की आमनसोल मे जो युनाइटेड आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन है तथा अन्य कई यूनियनो ने भी उनके बारे म सवाल उठाया था। मझे खुशी हुई कि वे चले गये, यह मामला खत्म हुआ।

दूसरा सवाल जो मधु लिमये जी ने उठाया था, उस पर जोर देना चाहता हू। काट्रेक्ट मजदूरो के बारे में आपकी नीति है कि हम काट्रेक्ट लेबर को खत्म कर देंगे, लेकिन नीति अपनी जगह पर है और काम ठीक उसके उलटा हो रहा है। काट्रेक्ट लेबर हटाने की माग ए०आइ०टी०यू०सी० या सी०पी०आइ० के लेबल से ही नही हो रही है, बल्कि आपकी आइ०एन०टी०यू०सी० की यूनियनों ने, जो ऐसे मजदूरो के अन्दर काम करती हैं, भी माग की है कि काट्रेक्ट लेबर हटा दिया जाय, लेकिन आज तक यह काम नही किया गया और वे बरकरार हैं। उनकी आड़ लेकर बडे बडे कुकर्म किये जा रहे है। जिन कुकर्मों को आप यदि खत्म करना चाहते है तो यह जरूरी हैं कि आप काट्रेक्ट लेबर प्रथा को समाप्त करे। जब तक आप ऐसा नही करेंगे तब तक तरह तरह की गडबडी चलती रहेगी और उनके नाम पर मजदूर विरोधी काम होते रहेंगे, कारखाना का लूट-खसोट भी चलती रहेगी।

तीसरी बात—जब आप ने इस कारखाने को मालिकों के हाथ से लिया, उसके पहले मालक उसका शोषण दोहन पूरी तरह से कर चुके थे, तमाम कारखाने को बरबाद कर चुके थे। जब आप ने उनके हाथ से इसे लिया तो इसके लिये आप ने उनको बडी रकम भी दी, लेकिन सारा रद्दी-रद्दी माल, उसके चलाने की जवाबदेही आप पर पडी। उस पर काफ़ी रुपया खर्च करने के बाद, जनता के पैसे को उस पर लगाने के बाद अब आप उसकी अवधि फिर 3 साल के लिये बढाने जा रहे हैं। दो साल हो चुके है, तीन साल की अवधि और बढ़ा रहे हैं, इस तरह कुल 5 साल के लिये आप उसको अपने हाथ मे रखना चाहते हैं। मेरी समझ मे नहीं आता—जब कि राष्ट्रीयकरण की नीति आप की घोषित नीति है तो फिर आप सीधे उसका राष्ट्रीयकरण क्यो नही कर रहे है, उसमे आप के सामने क्या झझट है, क्या घबराहट है, और इसको क्यो नही करना चाहते हैं या दूसरे तरीके से आप उन मालिकों की मदद करना चाहते हैं? क्या बात है, कोई न कोई बात जरूर होगी जिसकी वजह से आप राष्ट्रीयकरण से मुकर रहे है। अगर आपकी नीति ऐसी नही होती तो मैं समझ सकता था कि आपकी नीति नही है, लेकिन आप ने तो बहुत सी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया है, आगे भी करना चाहते हैं—तो फिर इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नही कर रहे है?

मै चाहता हू कि आप इन तीन मुद्दो के बारे मे बतलाये। आज भी वहां इस तरह के अनेक अफसर है—मैं चाहता हू कि उन तमाम लोगों के बारे मे जाच करवायें, जिनका रिकार्ड काला है, खराब है, बदनाम है। ऐसे लोगों को बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट मे बिल्कुल न रखिये, वरना जो लोग पहले कुकर्म करते थे, वे आज भी करेंगे और साथ में सरकार को बदनाम करेंगे, मजदूरो को बदनाम करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। इस लिये मैं इन तीनो बातो का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Sir I would be very brief and only take up certain points which I raised but, I feel, the same have not been fully dealt with by the hon. Minister. Yesterday, I had posed a question why was it necessary to change the system of management that had been evolved? Who were the Members of the previous Advisory Board and how many of them have been taken in the new board of mangement? Thirdly, in the statement circulated by the Ministry it is said that while substantial progress has been made a good deal still remains to be done and the programme for rehabilitating the plant and equipment will take longer than initially estimated. Therefore, I would like to know you say a good deal still remains to be done; this rehabilitation programme of Rs. 43 crores is still to be implemented and you come with piece-meal legislative proposal which only creates uncertainly. How can there be an integrated long-term development programme of this important sector of our economy. Fourthly, I would like to know, I know he is constrained on making any observations on the working of the SAIL But I quote from one of his observations which was to the effect that holding companies have become too big. They have to shed some burden and more responsibility will have to be given to the individual units I would like to know what would be the inter-relationship between SAIL and IISCO? How much autonomy will you give to the Administrator and how far over-lordism will continue from the bureaucratic set-up at Delhi? Please don't try to avoid answering this question because of the overpowering position of the SAIL. Sir, the last point which I would like to know from the hon. Minister is has any scheme been drawn up. What is the expectation of putting the Indian Iron and Steel Company on a very sure footing and to get real benefits for the advancement of the country so far as steel production is concerned? Are you satisfied with three years or have you got any long-term objects, which you ought to have by this time, of reviving the Indian Iron and Steel Company and placing it on a much much better footing. Please do not tinker with such important problems. Therefore, I would like to know, has any thought been given to these points,

SHRI K. D. MALAVIYA: Sir, I have nothing to add, in reply to what Mr Somnath Chatterjee has said, except that we are not tinkering with the problems of India Iron and Steel Company. We are taking a very comprehensive view as to what has to be done in future and we shall see to it that this public unit, which is now being looked after with lot of care by us, will stand on its own legs and serve the purpose for which it is meant. So far as long-term take over is concerned, I have already dealt with this question. I would not like to deal with it any more except to say that the time for take over has not yet come. Considering the critical time in resource position and looking into the interest of a large number of small shareholders, whom we could not gave much, let us stop talking about it.

As far as personalities are concerned, I would have very much wished Mr. Chatterjee has not raised that question.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am not criticising I would only like to know, how many members in the advisory board have been taken in the new board.

SHRI K. D. MALAVIYA: I do not have the details now. I will let you know. So far as personalities are concerned, it is in their interest we do not talk about it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am only asking the number.

SHRI K. D. MALAVIYA: With regard to the question of day to day interference from the top organisation. SAIL, I wish to reiterate what I have said that there is no day to day in-

terference from the holding company, which is known as SAIL. The object of the holding company, which is known as SAIL, is to coordinate, to have a long-term plan, to build its own expertise with regard to fulfilling long-term projects and to have liaison between the Ministry and the holding company from the point of view of relevant objects that we have before us.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Are you satisfied?

SHRI K. D. MALAVIYA: If I am satisfied with what is happening today, I will cease to function What I have said a few days back or a few weeks beck, holds good today It will be the constant endeavour of the Government to go on improving wherever we find that there are places to improve upon I do feel that the units, the steel mills, whether it is Rourkela or Bhilai or Bokaro or IISCO, must be given full authority to function They are functioning more or less on an autonomous basis But, during the gestation period, there are certain points where we cannot leave matters just by presuming that everything can be done in an automatic way Therefore, hon. Members will have to bear with us in the Ministry. We would see how this transitional process can be shortened, and more and more powers given to them We are transferring more and more powers to them Sometimes, when more powers are given to them, they make mistakes, then, the House comes on us demanding explanation and we have to say something by way of explanation as to what has happened. It is our duty, therefore, to get in touch with them to coordinate their activities, to oversee what is happening there and also, in certain respects, to monitor it I hope the period would be shortened With regard to what Mr. Ramavatar Shastri has said, I do not know what he meant.

शास्त्री जी ने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। कोई गड़बड़ तो हो नही रही है। खराब आदमी रहें ऐसा भी कुछ नहीं है।

कन्ट्रैक्ट लेबर की जहा तक बात है, मैं कह चुका हू कि मैनेजमेन्ट के प्रतिनिधि के साथ बैठ कर गवर्नमेन्ट के रिप्रेजेन्टेटिव ने यह निश्चय किया है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए लेकिन इस इन्टेरिम पीरियड मे कुछ समस्याये है जिनको वह भी महसूस करते है और हम भी महसूस करते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। इसमें अगर वह मेरे ऊपर दबाव न डाले तो अच्छा है।

और कोई बात उन्होंने कही नहीं है।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि बेलाडीला मे आयरन-ओर निकालने के लिए जो लेबर काम करते है वह ज्यादा निकालते है .

उपाध्यक्ष महोदय कहा बर्नपुर है, इसमे यह बेलाडीला कहा से आ गया ?

The question is:

"That the Bill be passed".

The Motion was adopted.

15.27 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL), 1974-75

DEMAND NO 8—DEPARTMENT OF FOOD

MR DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 125,00,00,000 on Revenue Account be granted to the

*Moved with the recommendation of the President.